...आभार माना।

नवभारत नगर की क्षतिग्रस्त पुलिया पर निगमायुक्त ध्यान दे

अपनी दुनिया 5.4.12

रतलाम। उकाला रोड़ पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण मार्ग बंद सा है। नवभारत नगर भी इसी क्षेत्र में है जो नाले से जुड़ा हुआ है,। नवभारत नगर की सड़कें भी टूटी हुई है तथा इससे जुड़ी हुई क्षतिग्रस्त पुलियां टूट कर आधी रह गई है। सैकड़ों वाहन आ जा रहे है। पुलिया पर वाहन निकालने में परेशानी होती है। संपर्क का मुख्य मार्ग यह कमजोर पुलिया कभी भी टूट सकती है जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। डा. दिनेश जोशी ने इस संबंध में निगमायुक्त का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही इस समस्या के निदान की मांग की है ताकि दुर्घटना की संभावना समाप्त हो सके और क्षेत्रवासियों के आने-जाने का मार्ग ठीक हो सके।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाः जिले से 23 अप्रैल को वैष्णो देवी की यात्रा

रतलाम। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आगामी 23 अप्रैल को जिले से वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री रवाना होंगे। रतलाम जिले के लिए शासन द्वारा 300 यात्रियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यात्रा के लिए आवेदन लेना प्रारंभ कर दिए गए हैं जो 15 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे।कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वैष्णो देवी यात्रा के लिए नियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार कर आवेदन प्राप्ति हेतु सभी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कारण अधिकारियों को निर्देशित किया है। यात्रा में डॉक्टर अटेंडर भी साथ रहेंगे। वैष्णो देवी यात्रा 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक संपन्न होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने एवं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला सूचना अधिकारी श्री नरेंद्रसिंह चौहान मोबाइल नंबर 99268-77636 या श्री महेश पोरवाल मोबाइल नंबर 99771-67429 पर संपर्क किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के इच्छुक हितग्राही अपने आवेदन अपनी जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जमा करा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी उन्हीं स्थानों से प्राप्त होगा।

अपनी दुनिया 5.4

हितग्राहियों के रुपए जमा का निरीक्षण करने गए थे आयुक्त

आवेदकों ने घेरा आयुक्त को, बोले रुपए होते तो पीएम आवास क्यों लेते

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क 6-4-22
patrika.com

रतलाम. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवंटित होने वाले आवास के लिए बैंक में हितग्राहियों से रुपये जमा करवाने का काम मंगलवार से शुरू हुआ। इस दौरान स्टेशन रोड स्थित बैंक में निरीक्षण के लिए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया पहुंचे तो लोगों ने उनको घेर लिया। लोगों ने कहा कि 3.30 लाख रुपये जमा करवाए जा रहे हैं, इतने रुपये होते तो पीएम आवास ही क्यों लेते।

स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दोपहर को निगम आयुक्त जैसे ही झारिया पहुंचे की कई हितग्राहियों ने उनको घेर लिया। एक - एक से बात करना आयुक्त ने शुरू किया। इस बीच कुछ हितग्राही पहुंचे व आयुक्त को घेर लिया। इनका आयुक्त से कहना था कि जितने रुपये मांगे जा रहे हैं, उतने रुपये होते तो पीएम आवास ही क्यों लेते।

हितग्राहियों ने बताया कि वे मजदूर हैं, उनसे वेतन की स्लीप मांगी जा रही है। जब मासिक वेतन ही तय नहीं है तो वेतन की स्लीप कौन देगा। सभी की बात सुनकर आयुक्त झारिया ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया।

गैरेज व पान सेंटर सील किए

दुकान सील करने की कार्रवाई करते हुए नगर निमम कर्मचारी। ●नईदुनिया

रतलाम। नगर निगम द्वारा गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने और अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मंगलवार को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही गंदगी करने पर मैक्सी ट्रैक्टर गैरेज महू रोड व बजरंग पान भंडार चांदनी चौक को सील किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कैलाश बर्फ भंडार, प्रजश से 5000-5000 रुपये, एस. मनीष से 1500 रुपये, राठौड़ रेस्टोरेंट, नीरज कंगन स्टोर, चंद्रप्रकाश सांकला, विकास प्रजापत, कपिल सोलंकी से 1000-1000 रुपये, अनवर, गुलाब राठौर से 250-250 रुपये, सोनू, ललित से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल द्वारा सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, राजकुमार भाटी आदि द्वारा की गई।

नई दुनिया 6-4-22

शहर के बगीचों की सुधरेगी सेहत

चार बगीचों के लिए 50 लाख रुपए मंजूर

पत्रिका इम्पैक्ट

निविदा जारी की जाएगी

शहर के बगीचों में सौंदर्यीकरण व सुधार के लिए योजना को अंतिम रुप दे दिया गया है व इसके लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी हो गई है। जल्दी ही निविदा जारी की जाएगी।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 6-4-22
patrika.com

रतलाम. शहर के बगीचों की सेहत को लेकर नगर निगम की बेरूखी के मामले को पत्रिका द्वारा उठाने के बाद कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने छोटे बच्चों के बगीचों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। शहर के चार बगीचों की दशा सुधारने के लिए 50 लाख रुपये मंजूर करते हुए सुधार का निर्णय लिया गया है।

शहर में नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार 120 बगीचे है। इन बगीचों के लिए स्थाई रुप से इतने ही माली है। इसके बाद भी कई बगीचों में संसाधन टूटे हुए है। पत्रिका ने सोमवार व मंगलवार के अंक में प्रमुखता से उठाया। इसके बाद कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार ने इस मामले में छोटे बच्चों के बगीचों के लिए संवेदनशीलता दिखाई है।

यहां होगा सुधार

त्रिवेणी रोड स्थित मानस भवन, विनोबा नगर, प्रतापनगर, हनुमान ताल के बगीचे के लिए राशि मंजूर कर ली गई है। इन क्षेत्र के बगीचों में 50 लाख रुपये की राशि से छोटे बच्चों के लिए संसाधन लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक अन्य पूर्व के बगीचे करमदी रोड स्थित अटल उद्यान का विस्तार किया जाएगा।

पत्रिका में प्रकाशित

पशु वाहन के 4 कर्मचारियों का 2-2 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पशु वाहन के नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह-भारतसिंह, मेहफुज-कालेखां, रामा व पूनमचन्द-रतन द्वारा 3 व 4 अप्रैल को 1 भी मवेशी नहीं पकड़ने पर 2-2 दिवस का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

गंदगी करने पर पांच दुकानें सील

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते है, खुले में यूरिन करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 अप्रैल सोमवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ महालक्ष्मी पान सेंटर, पुष्पा मसाला, निरंजन कंगन, बाबुलाल खिलौना माणक चौक व पिन्टू सायर चबुतरा द्वारा गंदगी करने पर दुकान सील की गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार राकेश पर 1000, बलराम चौहान, आनन्द शर्मा, पंकज अग्रवाल, सदा शंकर, तस्लीम व छोटू पर 500-500, राठौर टी स्टॉल पर 250, व भूरिया पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

काम में लापरवाही पर जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा का सात दिन का और 7 सफाई कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

आबकारी कंपाउंड में लगे कचरे के ढेर को लेकर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जोन प्रभारी एपी सिंह और दरोगा हिमाचल चावरे पर सात दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

इसके अलावा मंगलवार को सफाई व्यवस्था से बिना अनुमति और सूचना के अनुपस्थित रहे 7 सफाई कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा है। इनमें सुबह की शिफ्ट के 4 और दोपहर की शिफ्ट के 4 कर्मचारी शामिल हैं। उधर गंदगी फैलाने पर महू रोड स्थित मैक्सी ट्रैक्टर गैरेज महू रोड और चांदनीचौक के बजरंग पान भंडार की दुकान को सील कर दिया गया है। इसके अलावा कचरा फैलाने और अमानक पॉलीथिन का उपयोग करने पर 12 व्यक्तियों से स्पॉट फाइन भी वसूला गया। कार्रवाई स्पॉट फाइन दल के कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी ने की। 6-4-22

पशुओं के लिए रखा पानी का हौद जब्त करने पर गुस्साए लोग, वापस उतारना पड़ा

नगर निगम की स्पॉट फाइन टीम मनमानी कार्रवाई कर रही है। गुड़ी पड़वा पर जैन समाज की गोठ में स्टील बर्तनों का उपयोग होने पर भी डिस्पोजल के इस्तेमाल का जुर्माना लगाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ की मंगलवार को एक बार फिर स्पॉट फाइन दल को नागरिकों के गुस्सा का शिकार होना पड़ा। वाकया नाहरपुरा चौराहे का है, यहां रहवासियों ने पशुओं को पानी पिलाने के लिए सीमेंट का हौद रख रखा है। रहवासियों के अनुसार सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे कमिश्नर ने स्पॉट फाइन टीम को उसे हटाने को कहा। इस पर टीम ने हौद उठाकर गाड़ी में रख लिया। यह देख दुकानदार और रहवासी सुभाष जैन समेत अन्य विरोध करने लगे। मामला बढ़ता देख टीम को हौद वापस उतारकर रखना पड़ा।

नगर निगम का 34747 लाख रुपए का बजट पास, 3.50 लाख की बचत होगी

मिनी स्मार्ट सिटी और फूड जंक्शन के लिए अलग से फंड

भास्कर संवाददाता | रतलाम

2022-23 में नगर निगम 34747 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके विपरीत राजस्व और पूंजीगत स्रोतों से लगभग 34751 लाख की आय की उम्मीद जताई गई है। इस प्रकार निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 3.50 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान है।

लगातार तीसरी बार अफसरों द्वारा बनाए गए नगर निगम बजट को प्रशासक और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पास कर दिया है। अच्छी बात यह है कि नए बजट में किसी भी कर या शुल्क में इजाफा नहीं किया गया है। वहीं मिनी स्मार्ट सिटी में सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, रतलाम फूड जंक्शन सहित कुछ नई योजनाओं के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया है।

अमृत मिशन पार्ट-2 भी शामिल

बताया जा रहा है कि बजट में अमृत मिशन पार्ट-2 को भी शामिल किया गया है। इसमें पाइप लाइन सहित कुछ अन्य काम होंगे। वहीं नगर निगम गुलाब चक्कर का सौंदर्यीकरण भी कराएगा। बता दें कि अमृत मिशन के पहले चरण में सीवरेज सिस्टम का काम लगभग पूरा हो चुका है। तीन नालों को पक्का करने का काम अधूरा, जबकि सिटी ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट फेल होकर बंद हो चुका है। ग्रीन स्पेस वाले पार्ट में बगीचों का सौंदर्यीकरण निगम ने करा दिया है।

बीते साल 3.91 लाख की बचत हुई

2021-22 में नगर निगम को 3.91 लाख की बचत हुई है। बीते साल निगम को लगभग 33857 लाख रुपए की आय हुई। इसमें 16255 लाख राजस्व से और 17602 लाख पूंजीगत स्रोतों से मिले हैं। इसके विपरीत निगम ने 33853 लाख खर्च किए। इसमें 13323 लाख राजस्व पर और 20530 लाख पूंजीगत पर हुआ है।

भास्कर
6-4-22

ठेकेदार और निगमकर्मी के बीच विवाद, सड़क का काम बंद

रतलाम | जवाहर नगर मुक्तिधाम से लेकर डीडी नगर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार को ठेकेदार और एक निगमकर्मी में विवाद हो गया। यह इतना बड़ा की हाथापाई तक की नौबत आ गई। माजरा देख रहे आसपास के रहवासियों को बीच-बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि इसके बाद ठेकेदार और उसके कर्मचारी काम बंद करके चले गए। वजह, डामर, डंपर या अन्य सामग्री की क्वालिटी या गिनती को लेकर बताई जा रही है। 6-4.

क्षतिग्रस्त पुलिया से हादसे का अंदेशा

रतलाम। ऊंकाला रोड पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इसके कारण मार्ग बंद-सा है। नवभारत नगर भी इसी क्षेत्र में है, जो नाले से जुड़ा हुआ है। नवभारत नगर की सड़कें भी बदहला है तथा इससे जुड़ी हुई क्षतिग्रस्त पुलिया टूट कर आधी रह गई है। सैकड़ों वाहन आ जा रहे हैं। पुलिया पर वाहन निकालने में परेशानी होती है। पुलिया कभी भी पूरी तरह टूट सकती है। इससे हर समय हादसे का भय बना रहता है। डा. दिनेश जोशी ने इस संबंध में निगमायुक्त का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही इस समस्या के निदान की मांग की है। नई दुनिया

नवभारत नगर में क्षतिग्रस्त पुलिया से बचकर निकलते वाहन चालक।

6-4-22

गंदगी करने पर दो दुकानें सील की

पत्रिका 6-4

रतलाम. नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान अंतर्गत सख्ती का दौर जारी है। मंगलवार को शहर में अलग-अलग क्षेत्र में स्पाट फाइन दल द्वारा कार्रवाई करते हुए दो दुकाने सील की गई है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कुलदीप भट्ट वाले दल ने मैक्सी ट्रैक्टर गैरेज मऊ रोड व बजरंग पान सेंटर चांदनी चौक में गंदगी मिलने पर सील किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना...अब मिलेंगे 55 हजार रुपए

दुल्हन को 11 हजार का चेक और 38 हजार का सामान दिया जाएगा

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में राज्य सरकार ने प्रत्येक कन्या के हिसाब से 55 हजार रुपए देने का फैसला किया है। अब तक यह राशि 51 हजार रुपए थी। इसमें 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसमें से 6 हजार रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन करने वाले निकाय को दिए जाएंगे, 11 हजार रुपए का चेक कन्या को दिया जाएगा। साथ ही घर-गृहस्थी के लिए अच्छी क्वालिटी की सामग्री और गिफ्ट आदि के लिए 38 हजार रुपए आयोजक को दिए जाएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1414.83 करोड़ रुपए की अंशपूजी दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा 212.23 करोड़ रुपए होगा।
- पशुपालन के लिए किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के लिए बगैर ब्याज के 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को मंजूरी। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मंजूरी दी गई।
- मंदसौर जिले की कयामपुर सिंचाई परियोजना के लिए 2374 करोड़ रु मंजूर। सीतामऊ एवं मंदसौर तहसील के 252 ग्रामों की 1.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सुविधा मिल सकेगी।

6-4-22

परिवारों को किया डेरों में शिफ्ट

पत्रिका

रतलाम. लोकेन्द्र भवन रोड, अम्बेडकर मांगलिक भवन के पीछे व स्टेडियम की दुकानों के सामने वर्षों से अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले सांठिया व आदिवासी परिवारों को नगर निगम व पुलिस प्रषासन द्वारा बजरंग नगर व होमगार्ड कालोनी के डेरो में निगम के वाहनों से शिफ्ट किया है। इस दौरान अवैध गुमटी व चाय की दुकान भी हटाई गई। 6-4-22

सांठिया व आदिवासी परिवारों को किया डेरों में षिफ्ट

रतलाम। लोकेंद्र भवन रोड, आंबेडकर मांगलिक भवन के पीछे व स्टेडियम की दुकानों के सामने वर्षो से अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले सांठिया व आदिवासी परिवारों को नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा बजरंग नगर, होमगार्ड कालोनी के डेरो में निगम के वाहनों से शिफ्ट किया गया। इस दौरान अवैध गुमटी व चाय की दुकाने भी हटाई गई। नई दुनिया, 6-4

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रत्येक गांव में हो जल की पर्याप्त उपलब्धता

रतलाम। चालू ग्रीष्मकाल में किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं आए। प्रत्येक गांव की जानकारी संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त निर्देश समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने ताकीद की कि प्रत्येक एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता ग्रामीणों को सुनिश्चित हो, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को रतलाम शहर में भी पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर श्री एम.एल.आर्य, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा गेहूं उपार्जन पीडीएस से राशन वितरण की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्मकाल में पेयजल के संदर्भ में एसडीएम जनपद सीईओ तथा पीएचई को निर्देशित किया गया कि वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगामी मई तथा जून के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी इसका पूर्व आकलन प्रस्तुत करें। ग्रामवार डाटा संग्रहण किया जाए, संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम तथा जनपद के सीईओ प्रस्तुत करेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के व्यक्ति नेशन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैंप के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि जिले के 113 ट्राईबल हॉस्टल में कलेक्टर के निर्देशानुसार रंगरोगन तथा मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया गया कि कॉलोनाइजर्स के मामले में समीक्षा करते हुए अब तक जितने भी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर कराई गई है उनका फॉलोअप प्रस्तुत करें। जिले में स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए किए जा रहे नल कनेक्शन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इस संबंध में विद्युत उपलब्धता की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को संयुक्त रूप से एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन स्थापित कर दिए जाएं। स्वच्छता अभियान के संबंध में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों पर गंदगी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी दुकान पर गंदगी पाए जाने पर कम से कम 20 हजार रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 100 नवीन तालाबों का निर्माण किया जाना है। रतलाम जिले में भी उपरोक्त संख्या में तालाबों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करते हुए भूमि के अंतिम चयन की कार्यवाही 7 अप्रैल तक कर ली जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनसहयोग से भी तालाबों का निर्माण करवाया जाए। समय जगत

6-4-22

पैलेस रोड सिटी फोरलेन : अब चौथी बार टेंडर निकालने की तैयारी में निगम

निगम सिटी फोरलेन
यान दे रहा है। निगम के
कारियों का मानना है
इल्स पार्क, लॉजिस्टिक
की दिशा में शहर में
का जाल बिछेगा को
बेहतर तरीके से
होंगे। इसके लिए अब
णा प्रताप प्रतिमा याने
रोड से दो बत्ती होते हुए
रोड, मित्र निवास रोड
ड़ी तक, मित्रनिवास रोड
राहे तक सिटी फोरलेन
ा है। हालांकि रोड तो
गए, लेकिन इनके आस-
क्षेत्र में सौंदर्यीकरण की
अब तक ठोस कदम नहीं
उठाए गए हैं। ऐसे में इस रोड से सरपट तेज गति के वाहन तो दौड़ते हैं, लेकिन कुछ देर ठहराव का मन किसी का नहीं होता है।

अब फिर टेंडर की तैयारी

तत्कालीन महापौर पारस सकलेचा से लेकर डॉ. सुनीता यार्दे के कार्यकाल तक नगर निगम ने अलग-अलग समय इस मार्ग पर सिटी फोरलेन के टेंडर जारी किए। सबसे कम 60 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 1.80 करोड़ रुपये तक के टेंडर जारी किए गए। शुरू के दो बार में तो कोई टेंडर भरने ही नहीं आया। बाद में एक बार टेंडर कमेटी ही समय पर इसको पास नहीं कर पाई तो अंतिम बार टेंडर तो हो गए, लेकिन कोरोना काल आने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब 2019 के अंतिम टेंडर के बाद सिटी फोरलेन समय पर पूरा करवाने में फिसड्डी रही नगर निगम ने एक बार फिर नगर निगम से पैलेस रोड तक सिटी फोरलेन बनाने का सपना दिखाना शुरू किया है।

लागत बढ़ेगी इस बार

पूर्व के निकले टेंडर व इस बार फिर से निकलने वाले टेंडर में सिर्फ राशि की बढ़ोतरी रहेगी। पूर्व के टेंडर के मुकाबले इस बार टेंडर करीब 2 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि का रहेगा। इसमे चौड़ी रोड, ड्रेनेप लाइन, पानी की लाइन, बिजली के पोल आदि को शिफ्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा वॉकिंग के लिए पेवर ब्लॉक भी लगाए जाएंगे।

जल्दी बनेगी योजना

निवेशक आए तो शहर सुंदर लगे इसके लिए सिटी फोरलेन का जाल बिछाया जाएगा। नगर निगम से पैलेस रोड तक सिटी फोरलेन तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया, इसकी नई निविदा जारी करने की तैयारी की जा रही है।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

6-4-22

ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रत्येक गांव की जल उपल

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

सिंघम रिपोर्टर ❒ रतलाम

चालू ग्रीष्मकाल में किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं आए। प्रत्येक गांव की जानकारी संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त निर्देश समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने ताकीद की कि प्रत्येक एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता ग्रामीणों को सुनिश्चित हो, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को रतलाम शहर में भी पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा गेहूं उपार्जन पीडीएस से राशन वितरण की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्मकाल में पेयजल के संदर्भ में एसडीएम जनपद सीईओ तथा पीएचई को निर्देशित किया गया कि वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगामी मई तथा जून के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी इसका पूर्व आकलन प्रस्तुत करें। ग्रामवार डाटा संग्रहण किया जाए, संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम तथा जनपद के सीईओ प्रस्तुत करेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के व्यक्ति नेशन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैंप के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि जिले के 113 ट्राईबल हॉस्टल में कलेक्टर के निर्देशानुसार रंगरोगन तथा मरम्मत कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया गया कि कॉलोनाइजर्स के मामले में समीक्षा करते हुए अब तक जितने भी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर कराई गई है उनका फॉलोअप प्रस्तुत करें। जिले में स्कूलों

तथा आंग
के लिए वि
द्वारा की ग
प्राप्त नहीं हो
बाल विक
अधिकारी
संयुक्त रूप
कि सभी
आवश्यक
स्वच्छ

5-4-22

सीएम चौहान ने किया सीएम उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ

50 लाख तक के ऋण पर तीन फीसदी ब्याज की सब्सिडी

योजना प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और उम्मीदों का संदेश लेकर आई : सीएम

भोपाल, (प्रस)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण लेने वाले युवाओं को तीन प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी।

योजना में युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी, सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए 140 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार बैंकों में जमा करेगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है, उन परिवारों के युवा इस योजना में ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए नई आशा और उम्मीद का संदेश लेकर आई है। आज 2019 युवाओं को लगभग 108 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए। राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए एक यज्ञ के समान है। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के शुभारंभ अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर युवा के चेहरे पर मुस्कान हो, वह आत्म-विश्वास से परिपूर्ण हो। युवा आत्म-निर्भर बनें, राज्य सरकार रोजगार दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश में एक क्रांति का आरंभ है। आजीविका, व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए राज्य सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के लिए समग्र रूप से प्रयासरत है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए बैंक ऋण स्वीकृति-पत्र प्रदान किए।

हितग्राहियों से संवाद

मुख्यमंत्री ने भोपाल की सुश्री शुभांगनी श्रीवास्तव, दीपक नागर, खुशबू सिंह, राजगढ़ की श्रीमती पप्पी तंवर, विदिशा के विक्रम सिंह ठाकुर, नर्मदापुरम के आशीष और रेहटी, सीहोर के देवेंद्र मालवीय को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया।

आत्म-निर्भर मप्र के निर्माण में सहायक है सीएम के विचार : सखलेचा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के विचार के परिणाम स्वरूप ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का अंकुरण हुआ। युवाओं के स्वावलंबन के पक्षधर मुख्यमंत्री चौहान के विचार आत्म-निर्भर मप्र के निर्माण में सहायक हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद निर्णय : मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में बड़ा बदलाव

मप्र में बनेंगे 5 औद्योगिक क्षेत्र

भोपाल ● 5 अप्रैल (ब्यूरो) मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दी। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के मान से 55 हजार रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। इस राशि में से 6 हजार रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं 49 हजार रुपए की सामग्री कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जाएगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

32 हजार करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना - मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है।

ये निर्णय भी हुए

■ 2 हजार 373 करोड़ की लागत की मंदसौर जिले के कयामपुर में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। इसकी सिंचाई क्षमता 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर है।

■ सीतामऊ और मंदसौर तहसील के 200 गांवों को पाइप लाइन से सिंचाई करने का लाभ मिलेगा। ताकाजी सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

■ नगरीय निकायों में फायर सर्विसेस को निरंतर रखी जाएगी। इसमें 10 साल से पुरानी फायर ब्रिगेड को निकालकर नई फायर ब्रिगेड को खरीदने का निर्णय लिया है।

■ पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नए सरकारी दफ्तर बन सकेंगे।

■ विधि विभाग में एडवोकेट की लायब्रेरी के लिए 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए देना तय किया गया है।

■ सरकार छोटे पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के लिए 0 प्र. ब्याज पर लोन देगी।

■ जबलपुर हाईकोर्ट के लिए पांच नए पद सृजित किए गए हैं।

आज गोबर धन प्लांट का भूमिपूजन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण

भोपाल ● मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 6 अप्रैल को शाम 6 बजे गोबर धन प्लांट का भूमिपूजन, अमृत मिशन में निर्मित 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं जे.के. हॉस्पिटल के पास नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम जे.के. हॉस्पिटल के पास डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में होगा। नगर निगम भोपाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में भोपाल शहर से निकलने वाले 400 टन गीले कचरे एवं गोबर से बायो सी.एन.जी. निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है। गोबर धन प्लांट से आसपास के गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से होगी पुनः प्रारंभ - सुश्री ठाकुर

भोपाल ● मध्यप्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से पुनः प्रारंभ होगी। सुश्री ठाकुर ने यह बात यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पुनः सुचारु संचालन के लिए आयोजित बैठक में कही। बैठक में सुश्री ठाकुर ने सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, टीकमगढ़ और दमोह जिले के कलेक्टर और प्रभारी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से यात्रियों की आवेदन प्रक्रिया और स्टेशन तक यात्रियों को सुविधापूर्वक लाने के लिए निर्देशित किया।

6-4-22

सौगात

मंत्री परिषद ने रतलाम के लिए ₹ 462 करोड़ स्वीकृत किए

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. प्रदेश मंत्री परिषद ने औद्योगिक पार्क रतलाम फेस 1 का विकास करने हेतु 462 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति पर शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने रतलाम प्रवास के दौरान रतलाम औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु बजट में राशि का जल्द प्रावधान करने की घोषणा की थी। इसके बाद मंत्रीपरिषद की बैठक में प्रदेश के जिन पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 714.5 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उसमें रतलाम औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए सर्वाधिक 462 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 6-4-22

काश्यप ने बताया कि रतलाम औद्योगिक पार्क के विकास के लिए प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग को 1400 हेक्टेयर भूमि पहले ही हस्तांतरित कर दी गई हैं। इस भूमि पर मप्र औद्योगिक विकास निगम विकास कार्य करेगा। मेगा औद्योगिक पार्क में 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि का पूंजि निवेश होने की संभावना है। इससे 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यह पार्क रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र बनाने में सहायक होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा सहित अन्य ने इस मंजूरी पर हर्ष व्यक्त किया है।

जोन प्रभारी सहित अन्य का वेतन काटा

पत्रिका

रतलाम. शहर में स्वच्छता अभियान में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के झोन प्रभारी एपीसिंह, दारोगा हिमाचल चांवरे का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश आयुक्क्त सोमनाथ झारिया ने दिए है। इसके अलावा नगर निगम पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में सुबह 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति की जांच की गई। सुबह 3 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गए। इसके बाद निगम आयुक्त झारिया ने एक व आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। 6-4-22

ना जाने कब बनेगा सिटी फोरलेन

नगर निगम से पैलेस रोड सिटी फोरलेन: अब चौथी बार टेंडर निकालने की

पत्रिका बिग इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम सिटी फोरलेने के निर्माण के प्रति कितना संजीदा है, यह इसी से साबित हो जाता है कि नगर निगम तिराहे से लेकर राजमहल याने की पैलेस रोड तक बनने वाले सिटी फोरलेन के लिए चौथी बार टेंडर जारी किए जाएंगे। टेंडर निकालने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है।

शहर में विकास के दावों के बीच नगर निगम सिटी फोरलेन बनाने पर ध्यान दे रहा है। निगम के आला अधिकारियों का मानना है कि टेक्सटाइल्स पार्क, लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में शहर में बेहतर रोड का जाल बिछेगा को निवेशक बेहतर तरीके से आकर्षित होंगे। इसके लिए अब तक महाराणा प्रताप प्रतिमा याने की सैलाना रोड से दो बत्ती होते हुए मित्रनिवास रोड, मित्र निवास रोड से सालाखेड़ी तक, मित्रनिवास रोड से कोर्ट तिराहे तक सिटी फोरलेन बनाया गया है। हालांकि रोड तो बना दिए गए, लेकिन इनके आस-पास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए है। ऐसे में इस रोड से सरपट तेज गति के वाहन तो दौड़ते है, लेकिन कुछ देर ठहराव का मन किसी का नहीं होता है।

अब फिर टेंडर की तैयारी

तत्कालीन महापौर पारस सकलेचा से लेकर डॉ. सुनीता यार्दे के कार्यकाल तक नगर निगम ने अलग-अलग समय इस मार्ग पर सिटी फोरलेन के टेंडर जारी किए। सबसे कम 60 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 1.80 करोड़ रुपये तक के टेंडर जारी किए गए। शुरू के दो बार में तो कोई टेंडर भरने ही नहीं आया। बाद में एक बार टेंडर कमेटी ही समय पर इसको पास नहीं कर पाई तो अंतिम बार टेंडर तो हो गए, लेकिन कोरोना काल आने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब 2019 के अंतिम टेंडर के बाद सिटी फोरलेन समय पर पूरा करवाने में फिसड्डी रही नगर निगम ने एक बार फिर नगर निगम से पैलेस रोड तक सिटी फोरलेन बनाने का सपना दिखाना शुरू किया है।

लागत बढ़ेगी इस बार

पूर्व के निकले टेंडर व इस बार फिर से निकलने वाले टेंडर में सिर्फ राशि की बढ़ोतरी रहेगी। पूर्व के टेंडर के मुकाबले इस बार टेंडर करीब 2 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि का रहेगा। इसमे चौड़ी रोड, ड्रेनेप लाइन, पानी की लाइन, बिजली के पोल आदि को शिफ्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा वॉकिंग के लिए पेवर ब्लॉक भी लगाए जाएंगे।

जल्दी बनेगी योजना

निवेशक आए तो शहर सुंदर लगे इसके लिए सिटी फोरलेन का जाल बिछाया जाएगा। नगर निगम से पैलेस रोड तक सिटी फोरलेन तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया, इसकी नई निविदा जारी करने की तैयारी की जा रही है।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

6-4-22

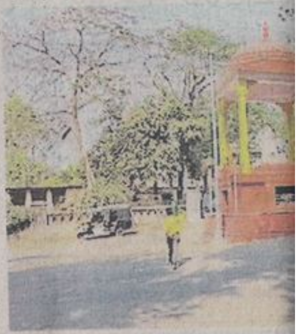

पांच जिलों में होगा 32 हजार करोड़ का निवेश

कैबिनेट में स्वीकृति ● रतलाम, धार, भोपाल, सीहोर व नरसिंहपुर में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए रतलाम, धार, भोपाल, सीहोर और नरसिंहपुर में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। यहां 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इससे 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, वहीं उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भोपाल (बैरसिया), सीहोर (आष्टा झिलेला), धार (तिलगारा), रतलाम और नरसिंहपुर में एक हजार 997 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर निवेशकों ने भूखंड आवंटन में रूचि दिखाई है। प्रारंभिक तौर पर विभिन्न उद्योग समूहों के साथ जो चर्चा हुई है, उसमें 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना मोहासा बाबई के स्थान पर विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में की जाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कारिडोर के निकट किसी अन्य विकल्प पर विचार करने के लिए पत्र लिखा था। इस आधार पर विक्रम उद्योगपुरी का चयन किया गया है। यह देवास रोड पर स्थित है और इसके लिए 532 एकड़ भूमि उपलब्ध है। बैठक में एक प्रस्ताव यह भी था कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के चार पद निर्मित किए जा[…] लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर ब[…] में विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज की मौजूदगी में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- राज्यपाल का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया गया। अब वे प्रति प्रकरण 50 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये स्वीकृत कर सकेंगे।
- गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से दो लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण मिलेगा।
- नगरीय क्षेत्रों में फायर सर्विस की योजना को निरंतर रखने, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज रहित ऋण देने, धान की मिलिंग के लिए अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- आग की रोकथाम के लिए फायर सर्विसेज योजना को निरंतर रखा जाएगा। दस साल पुराने 326 वाहन की जगह नए लिए जाएंगे।
- राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के क्षेत्राधिकार में आने वाला बैतूल जिला अब बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में अंतर्गत आएगा।
- मंदसौर जिले की कायमपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। 252 गांवों के एक लाख 12 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।
- मंदसौर जिले की ताखाजी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। नौ गांवों का तीन हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।
- बालाघाट जिले की लामटा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। 55 गांवों में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

38 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की होगी स्थापना

ग्रामीण बैंकों में 212 करोड़ रुपये का निवेश

प्रदेश सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 212 करोड़ रुपये का निवेश अंशपूंजी के तौर पर करेगी। केंद्र सरकार ने एक हजार 414 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता स्वीकृत की है। इसके लिए राज्यांश मिलाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में निर्णय लिया गया। प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यवसाय 40 हजार करोड़ रुपये का है।

विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय की भूमि पुनर्घनत्वीकरण के दायरे में

प्रदेश के विश्वविद्यालय, अकादमियां और नगरीय निकायों के स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्घनत्वीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य के बाहर सरकार की अविवादित और अनुपयोगी भूमि पर भी योजना लागू होगी।

तीर्थ दर्शन के लिए अलग-अलग जाएंगे मंत्री

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में मंत्री एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर जाने वाली ट्रेन के साथ मंत्री जाएंगे। पहले प्रस्ता[व] था कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री एक सा[थ] 18 अप्रैल को ट्रेन से काशी कारिडोर, गंगा स्नान सहित अन्य स्थान पर जाएंगे।

6-4-2

औद्योगिक विकास की दिशा में रतलाम को बड़ी सौगात • मंगलवार को मंत्री परिषद ने दी स्वीकृति

462 करोड़ से होगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन फेस-1 का विकास, मंजूरी मिली

रंग लाया विधायक काश्यप का प्रयास, प्रदेश के 5 नए औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा रतलाम को मिला

भास्कर संवाददाता | रतलाम

ग्राम जुलवानिया से बिबड़ौद तक बनने जा रहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के फेस वन के डेवलपमेंट के लिए मंगलवार को मध्यप्रदेश मंत्री परिषद ने 462 करोड़ की मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह कि मंत्री परिषद ने प्रदेश के जिन पांच नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने 714.56 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी है, उसमें अकेले रतलाम के लिए 462 करोड़ रुपए हैं। इसके पीछे बड़ी भूमिका विधायक चेतन्य काश्यप की रही। 1466 हेक्टेयर में फैले विशेष निवेश क्षेत्र का डेवलपमेंट तीन हिस्सों में होना है।

करीब 766 हेक्टेयर जमीन फार्मा, प्रोडक्शन, एजूकेशन, डीपी समेत सभी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए रहेगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब और मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनेगा। लॉजिस्टिक हब के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को जमीन आवंटित हो चुकी है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क का प्रपोजल (मित्रा) योजना में मंजूरी के लिए केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। इसे मप्र औद्योगिक विकास निगम विकसित करेगा। योजना के मुताबिक मेगा औद्योगिक पार्क में 25 हजार करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है।

तीन चरण : ऐसे होगा मेगा औद्योगिक पार्क का विकास

निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित नक्शा।

- **मेगा टेक्सटाइल पार्क**- केंद्र सरकार की मेगा इंवेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (मित्रा) योजना में देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना हैं। रतलाम का लगभग 300 हेक्टेयर का यह पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा होगा। कंसल्टेंट कंपनी ने प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है।
- **लॉजिस्टिक हब**- यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होगा, जो करीब 400 हेक्टेयर में फैला होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जमीन अलॉट हो गई है। दिल्ली की कंसल्टेंट कंपनी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रही है।
- **इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन**- यह करीब 766 हेक्टेयर में फैला होगा। इसका नक्शा तैयार हो चुका है। इसका डेवलपमेंट निवेशक की जरूरत के हिसाब से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग करेगा। सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं भी जुटाएगा।

6-4-22

भीलवाड़ा और बिहार की कंपनियां भी करेंगी निवेश

मेगा औद्योगिक पार्क में भीलवाड़ा और बिहार की कंपनियां भी निवेश करेंगी। इसके लिए दोनों कंपनियां एमपीआईडीसी से बात कर रही हैं। पहले राजस्थान की झील रेनी वियर कंपनी 50 हेक्टेयर जमीन की डिमांड कर चुकी है। अलॉटमेंट के लिए कंपनी के संचालक विधायक चेतन्य काश्यप से मुलाकात भी कर चुके हैं।

विधायक काश्यप ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

औद्योगिक पार्क के फेस 1 का विकास करने 462 करोड़ रुपए मंजूर करने पर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी 2021 को रतलाम प्रवास के दौरान औद्योगिक पार्क के लिए बजट में प्रावधान करने की घोषणा की थी।

यह पार्क रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र बनाने में सहायक होगा। तीन कंपनियां निवेश के लिए आगे आ चुकी हैं। लॉजिस्टिक हब और मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी भी जल्द मिल जाएगी। निवेश क्षेत्र से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही आसपास के गांवों का भी डेवलपमेंट होगा।

चेतन्य काश्यप, विधायक

ष्टिगत प्रत्येक गांव की जल उपलब्धता जानकारी प्रस्तुत करें

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर .एल.आर्य, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम शेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद आदि स्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा गेहूं उपार्जन पीडीएस राशन वितरण की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्मकाल में पेयजल संदर्भ में एसडीएम जनपद सीईओ तथा पीएचई को र्देशित किया गया कि वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगामी ई तथा जून के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी इसका र्व आकलन प्रस्तुत करें। ग्रामवार डाटा संग्रहण किया जाए, युक्त रिपोर्ट एसडीएम तथा जनपद के सीईओ प्रस्तुत करेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के व्यक्ति नेशन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैंप के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि जिले के 113 ट्राईबल हॉस्टल में कलेक्टर के निर्देशानुसार रंगरोगन तथा मरम्मत कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया गया कि कॉलोनाइजर्स के मामले में समीक्षा करते हुए अब तक जितने भी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर कराई गई है उनका फॉलोअप प्रस्तुत करें। जिले में स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए किए जा रहे नल कनेक्शन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इस संबंध में विद्युत उपलब्धता की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को संयुक्त रूप से एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन स्थापित कर दिए जाएं।

स्वच्छता अभियान के संबंध में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों पर गंदगी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी दुकान पर गंदगी पाए जाने पर कम से कम 20 हजार रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 100 नवीन तालाबों का निर्माण किया जाना है। रतलाम जिले में भी उपरोक्त संख्या में तालाबों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करते हुए भूमि के अंतिम चयन की कार्यवाही 7 अप्रैल तक कर ली जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनसहयोग से भी तालाबों का निर्माण करवाया जाए।

25-4-22

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

25 तक फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करें-कलेक्टर

रतलाम ● स्वदेश समाचार 6-4-22

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया, संचालन तथा प्रारूप मतदाता सूची, जांच सूची, डुप्लीकेट सूची सहित दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई।

अपर कलेक्टर तथा उपजिला निर्वाचन अधिकारी एम.एल. आर्य की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई। श्री आर्य ने बताया कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आगामी 25 अप्रैल तक फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जाना है। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का 4 अप्रैल को जिले की सभी नगरीय निकायों के वार्ड व तथा पंचायतों में विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन किया गया है। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे- आपत्ति प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दावा-आपत्ति केंद्रों पर 11 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे। आयोग द्वारा दावा-आपत्ति के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेंगे। बताया गया कि प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरीय निकाय पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन आगामी 25 अप्रैल को किया जाना है। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, नियमों की जानकारी विस्तृत रूप से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई।

नवभारत नगर की क्षतिग्रस्त पुलिया पर निगमायुक्त ध्यान दे

रतलाम। उंकाला रोड़ पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण मार्ग बंद सा है। नवभारत नगर भी इसी क्षेत्र में है जो नाले से जुड़ा हुआ है,। नवभारत नगर की सड़कें भी टूटी हुई है तथा इससे जुड़ी हुई क्षतिग्रस्त पुलिया टूट कर आधी रह गई है। सैकड़ों वाहन आ जा रहे है। पुलिया पर वाहन निकालने में परेशानी होती है। संपर्क का मुख्य मार्ग यह कमजोर पुलिया कभी भी टूट सकती है जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। डा. दिनेश जोशी ने इस संबंध में निगमायुक्त का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही इस समस्या के निदान की मांग की है ताकि दुर्घटना की संभावना समाप्त हो सके और क्षेत्रवासियों के आने-जाने का मार्ग ठीक हो सकें।

श्री राम नवमी के अवसर पर रतलाम में होगा प्राकट्य पर्व का आयोजन

रतलाम। शासन के निर्देशानुसार आगामी 10 अप्रैल को श्री राम नवमी के पावन अवसर पर रतलाम में प्राकट्य पर्व का आयोजन होगा जिसका शुभारंभ शाम 7 बजे से कालिका माता उद्यान प्रांगण में किया जाएगा।

5-4-22 सिंहासन

आशियाना • 18 अप्रैल तक होगा रजिस्ट्रेशन, बैंक में राशि जमा होने की तारीख और समय के आधार पर बनेगी हितग्राहियों की वरीयता सूची

पीएम आवास योजना : पहले ही दिन 1.34 करोड़ भरकर 311 लोगों ने बुक कराए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, 420 में से अब सिर्फ 109 ही बचे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सिटी के नॉन स्लम एरिया के 420 परिवारों को बारिश से खुद का आशियाना मिल जाएगा। डोसीगांव और बंजली में पीएम आवास योजना में बन चुके या बन रहे 420 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन मंगलवार से प्रारंभ हुए। पहले ही दिन 2240 आवेदकों में से 311 परिवारों ने 1.34 करोड़ रुपए जमा करके फ्लैट्स बुक करा लिए हैं। इनमें 303 परिवारों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 35000 रुपए, जबकि 8 परिवारों ने 3.50 लाख का पूरा अंशदान एक साथ जमा करा दिया। इस तरह अब सिर्फ 109 फ्लैट्स की बुकिंग होना बाकी है।

इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हितग्राहियों के पास 18 अप्रैल तक का समय है। ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने पर हितग्राहियों की वरीयता का चयन बैंक में राशि जमा होने के दिनांक व समय के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया जाएगा। वहीं पूरा अंशदान एक मुश्त जमा कराने वाले को फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले परिवारों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर टैंट लगाने के साथ अन्य व्यवस्था भी की है।

बाकी हितग्राही शामिल होंगे वेटिंग लिस्ट में

बैंक में पक्के मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हितग्राही परिवार।

अफोंडेबल हाउस (एएचपी) घटक में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स से ज्यादा रजिस्ट्रेशन राशि जमा होने पर पहले तो वरीयता के आधार पर 420 मकान का आवंटन किया जाएगा। बाकी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इन्हें नए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनने पर सूची अनुसार मकान आवंटन होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क लौटाया जाएगा या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ है।

ऐसे मिलेगा फ्लैट

- 18 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चलेगा।
- 20 अप्रैल तक हितग्राहियों को जमा राशि का विवरण नगर निगम के सिविक सेंटर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में देना पड़ेगा।
- इसके आधार पर वरीयता सूची बनकर फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।

शहर में पीएम आवास योजना अब तक

योजना	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी
डोसीगांव प्रथम चरण	396	96	0
डोसीगांव द्वितीय चरण	196	144	0
मुखर्जी नगर	36	0	96
बंजली	224	192	0
अब तक बन चुके	852	432	96

6-4-22

हितग्राही परिवारों में खासा उत्साह है। पहले ही दिन 311 ने राशि जमा कराई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही फ्लैट्स आवंटन करना शुरू कर देंगे। डोसीगांव के बाद बंजली के 224 फ्लैट्स का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। डोसीगांव में शिवशंकर बस्ती के 332 परिवार फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। **चेतन्य काश्यप,** विधायक

कैबिनेट की मंजूरी: 55 हजार रुपए मिलेंगे

श्रम विभाग से हटाई योजना, सामाजिक न्याय कराएगा कन्या विवाह

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 6-4-22
patrika.com

भोपाल. कन्या विवाह व निकाह योजना सामाजिक न्याय विभाग से संचालित होगी। इसे श्रम विभाग से हटा लिया गया है। कन्या विवाह में कोरोना काल के दौरान गड़बड़ी के बाद सरकार ने एक ही विभाग के तहत चलाना तय किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी।

कन्या विवाह की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार कर दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इसे मंजूर किया गया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 49 हजार रुपए कन्या को मिलेंगे। 6 हजार रुपए आयोजनकर्ता को मिलेंगे। योजना में फिलहाल जिला व जनपद स्तर पर आवेदन करना होंगे।

ये भी निर्णय: पशुपालन को बढ़ाने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 2 लाख तक कर्ज। 2374 करोड़ की मंदसौर-कयामपुर सिंचाई परियोजना मंजूर। 46.86 करोड़ की मंदसौर-ताखजी सिंचाई परियोजना मंजूर। 146.50 करोड़ की लामटा पाइप इरीगेशन नेटवर्क परियोजना मंजूर।

बैंकों को सहायता

केंद्र ने प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में 1414.83 करोड़ मंजूर किए हैं। राज्य का हिस्सा 212.23 करोड़ है। इसके चलते कैबिनेट ने इस राशि की मंजूरी दी गई है।

पुनर्घनत्वीकरण

पुनर्घनत्वीकरण 2016 की योजना में संशोधन कर यूनिवर्सिटी, अकादमी और नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। सरकार चाहेगी तो इन जगहों पर पुनर्विकास कर सकेगी। प्रदेश के बाहर की संस्थाओं की संपत्ति-जमीन को भी पुनर्घनत्वीकरण के दायरे में लिया गया है। पर्यवेक्षक एजेंसी के तौर पर टीएनसीपी, पीडब्ल्यूडी-पीएलयू, एमपीआरडीसी व निकाय थे। अब साधिकार समिति को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो किसी अन्य एजेंसी को भी पर्यवेक्षक बना सकेगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: जिले से 23 अप्रैल को वैष्णो देवी की यात्रा

रतलाम। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आगामी 23 अप्रैल को जिले से वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री रवाना होंगे। रतलाम जिले के लिए शासन द्वारा 300 यात्रियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यात्रा के लिए आवेदन लेना प्रारंभ कर दिए गए हैं जो 15 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वैष्णो देवी यात्रा के लिए नियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार कर आवेदन प्राप्ति हेतु सभी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कारण अधिकारियों को निर्देशित किया है। यात्रा में डॉक्टर अटेंडर भी साथ रहेंगे। वैष्णो देवी यात्रा 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक संपन्न होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने एवं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला सूचना अधिकारी श्री नरेंद्रसिंह चौहान मोबाइल नंबर 99268-77636 या श्री महेश पोरवाल मोबाइल नंबर 99771-67420 पर संपर्क किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के इच्छुक हितग्राही अपने आवेदन अपनी जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जमा करा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी उन्हीं स्थानों से प्राप्त होगा। 6-4-22

मुख्यमंत्री आज करेंगे गोबर धन प्लांट का भूमि-पूजन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 अप्रैल को शाम 6 बजे गोबर धन प्लांट का भूमि-पूजन, अमृत मिशन में निर्मित 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं जे.के. हॉस्पिटल के पास नव-निर्मित पुल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम जे.के. हॉस्पिटल के पास डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में होगा। नगर निगम भोपाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में भोपाल शहर से निकलने वाले 400 टन गीले कचरे एवं गोबर से बायो सी.एन.जी. निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है। गोबर धन प्लांट से आस-पास के गाँवों को जोड़ा जायेगा, जिससे किसानों को जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट से निर्मित बायो सी.एन.जी. लगभग 250 सिटी बसों को मार्केट रेट से 5 रुपए कम पर मिलेगी। प्रतिवर्ष एक लाख 5 हजार टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी। प्लांट की स्थापना में अनुमानित खर्च 80 करो[illegible] रुपए आयेगा, जो कार्यरत [illegible] द्वारा ही वहन किया [illegible]

निगम के दल ने की किया गैरेज, पान सेंटर सील

रतलाम। नगर निगम के दल द्वारा स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया। साथ ही गंदगी करने पर मैक्सी ट्रेक्टर गैरेज महू रोड व बजरंग पान भण्डार चांदनी चौक को सील किया गया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कैलाश बर्फ भण्डार व प्रजश पर 5000-5000, एस मनीष पर 1500, राठौड़ रेस्टोरेंट, नीरज कंगन स्टोर, चन्द्रप्रकाश सांकला, विकास प्रजापत, कपील सोलंकी पर 1000-1000, अनवर व गुलाब राठौर पर 250-250, सोनू व ललीत पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन किया। कार्यवाही कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस अब 9 को

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को प्रातः 11.30 बजे कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पूर्व में यह कॉन्फ्रेंस 8 अप्रैल को आयोजित होनी थी। कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उक्त वीडियो कांफ्रेंस में शामिल होंगे।

ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रत्येक गांव की जल उपलब्धता जानकारी प्रस्तुत करें

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

रतलाम। चालू ग्रीष्मकाल में किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं आए। प्रत्येक गांव की जानकारी संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त निर्देश समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने ताकीद की कि प्रत्येक एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता ग्रामीणों को सुनिश्चित हो, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को रतलाम शहर में भी पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद आदि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा गेहूं उपार्जन पीडीएस से राशन वितरण की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्मकाल में पेयजल के संदर्भ में एसडीएम जनपद सीईओ तथा पीएचई को निर्देशित किया गया कि वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगामी मई तथा जून के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी

इसका पूर्व आकलन प्रस्तुत करें। ग्रामवार डाटा संग्रहण किया जाए, संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम तथा जनपद के सीईओ प्रस्तुत करेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के व्यक्ति नेशन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैंप के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि जिले के 113 ट्राईबल हॉस्टल में कलेक्टर के निर्देशानुसार रंगरोगन तथा मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया गया कि कॉलोनाइजर्स के मामले में समीक्षा करते हुए अब तक जितने भी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर कराई गई है उनका फॉलोअप प्रस्तुत करें। जिले में स्कूलों तथा आंगनवाडियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए किए जा रहे नल कनेक्शन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इस संबंध में विद्युत उपलब्धता की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को संयुक्त रूप से एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, आंगनवाडियों में नल कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन स्थापित कर दिए जाएं।

स्वच्छता अभियान के संबंध में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों पर गंदगी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी दुकान पर गंदगी पाए जाने पर कम से कम 20 हजार रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 100 नवीन तालाबों का निर्माण किया जाना है। 5-4-22

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

प्रत्येक गांव की जल उपलब्धता जानकारी प्रस्तुत करें

निगम आयुक्त से अवैध कालोनी के मामले में रिपोर्ट देने को कहा

● रतलाम।

चालू ग्रीष्मकाल में किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं आए। प्रत्येक गांव की जानकारी संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने उक्त निर्देश समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने ताकीद की कि प्रत्येक एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता ग्रामीणों को सुनिश्चित हो, साथ ही जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग करें।

कलेक्टर ने निगम आयुक्त को रतलाम शहर में भी पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर श्री एम.एल.आर्य, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त श्री झारिया को निर्देशित किया गया कि कॉलोनाइजर्स के मामले में समीक्षा करते हुए अब तक जितने भी कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर कराई गई है उनका फॉलोअप प्रस्तुत करें। जिले में स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए किए जा रहे नल कनेक्शन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इस संबंध में विद्युत उपलब्धता की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को संयुक्त रूप से एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन स्थापित कर दिए जाएं। स्वच्छता अभियान के संबंध में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों पर गंदगी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी दुकान पर गंदगी पाए जाने पर कम से कम 20 हजार रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 100 नवीन तालाबों का निर्माण किया जाना है। रतलाम जिले में भी उपरोक्त संख्या में तालाबों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करते हुए भूमि के अंतिम चयन की कार्यवाही 7 अप्रैल तक कर ली जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनसहयोग से भी तालाबों का निर्माण करवाया जाए।

मई तथा जून के दौरान की स्थिति का पूर्व आंकलन प्रस्तुत करें

बैठक में कलेक्टर द्वारा गेहूं उपार्जन पीडीएस से राशन वितरण की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्मकाल में पेयजल के संदर्भ में एसडीएम जनपद सीईओ तथा पीएचई को निर्देशित किया गया कि वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगामी मई तथा जून के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी इसका पूर्व आंकलन प्रस्तुत करें। ग्रामवार डाटा संग्रहण किया जाए, संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम तथा जनपद के सीईओ प्रस्तुत करेंगे। 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के व्हाक्सिनेशन की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक कैंप के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। बैठक में जनजाति कार्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि जिले के 113 ट्राईबल हॉस्टल में कलेक्टर के निर्देशानुसार रंगरोगन तथा मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

दशनिनाद 5-4-22